संख्या- 1/2015/40/1(20)2014/35-3-2015

प्रेषक,

नवीन चन्द्र त्रिपाठी,
विशेष सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेंवा में

जिलाधिकारी,
पीलीभीत।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांक 15 जनवरी, 2015**

विषयः वर्ष 2014-15 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत बाढ़ रेस्क्यू सेल्टर का निर्माण मद हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह की कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में जनपद- पीलीभीत में बाढ़ रेस्क्यू सेल्टर के निर्माण की निम्नलिखित परियोजनाओं हेतु रू.36.50 लाख (रू. छत्तीस लाख पच्चास हजार मात्र) की लागत सहित प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये, उनके लिये रू.36.50 लाख (रू. छत्तीस लाख पच्चास हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है।

(धनराशि लाख रू.)

विकास खण्ड का नाम	क्र.स.	परियोजना का नाम कार्यदायी संस्था - लोक निर्माण विभाग	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
पूरनपुर	1.	सीमा सुरक्षा चौकी नजुला नक्टा बाढ़ रेस्क्यू सेल्टर का निर्माण	18.25	18.25
	2.	सीमा सुरक्षा चौकी लग्गा-भग्गा-।। बाढ़ रेस्क्यू सेल्टर का निर्माण।	18.25	18.25
		योग	36.50	36.50

1- अवमुक्त धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी जिसके लिये स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा । परियोजना/ योजना पर किया जाने वाला व्यय स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा ।

2- स्वीकृत कार्य को प्रारम्भ करने के लिये अधिकृत कार्यदायी संस्था को यथाशीध्र कार्य-आदेश निर्गत किया जायेगा, जिसके साथ अनुमोदित आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) की एक प्रति कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी ।

3- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसी कार्य के लिये पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत/ स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गई है तथा न ही ये कार्य किसी अन्य कार्यक्रम की कार्य-योजना में सम्मिलित है ।

4- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्थलीय निरीक्षण उपरान्त विस्तृत आगणन तैयार करते हुये कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। विस्तृत आगणन यदि अनुमोदित मूल आगणन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न (Significantly different) होते है, तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन स्तर से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- कार्यदायी संस्था द्वारा कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर कोटेशन के माध्यम से दरें प्राप्त की जायेगी । कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री /उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज/वित्तीय नियमों तथा आदेशों के अन्तर्गत किया जायेगा ।

6- कार्य का निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुये समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगी । इस संदर्भ में अधिकृत थर्ड पार्टी निरीक्षणकर्ता को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा ।

7- कार्य-स्थल पर इसे बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ कार्य के मुख्य विवरण शिलापट्ट/ बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेगें।

8- द्विरावृत्ति से बचने के लिये कार्य से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के बाद वीडियोग्राफी भी कराई जायगी ।

9- उक्त परियोजनाओं से सृजित परिसंपत्तियों का अनुरक्षण सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा अपने संसाधनों से एवं आवश्यकतानुसार बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध धनराशि से कायर्दायी संस्थाओं के सहयोग से किया जायेगा। साथ ही परियोजनाओं के पूर्व होने तथा सृजित परिसंपत्तियों का सम्बन्धित को हस्तान्तरण का प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी द्वारा नियोजन विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा।

10- अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से एवं विलम्बतम् 31 मार्च, 2015 तक कर लिया जाय। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय कार्य की भौतिक प्रगति के विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियाजन विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कार्य हेतु राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार,उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा। तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात तीन माह में अर्थात दिनांक 30 जून, 2015 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुये व्यय का महालेखाकार द्धारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

11- भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार, जारीकी जा रही धनराशि 15 दिन के अन्दर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जाना सुनि" किया जायेगा।

12- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीध्र उपलब्ध करवाया जायेगा।

13- समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्श सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40 के अर्न्तगत संलग्नक मे सम्बन्धित लेखाशीर्ष के अर्न्तगत सुसंगत मदों के नामें डाला जायेगा। उक्त लेखाशीर्ष मे प्रश्नगत धनराशि अनुदान संख्या-40-आयोजनागत-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूजीगंत परिव्यय -06-बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम-800-अन्य व्यय -10 बाढ़ शरणालय के निर्माण के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24- वृहत निर्माण कार्य मे 4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूजीगंत परिव्यय–06- बार्डर एरिया डेवलपमेट कार्यक्रम-337- सड़क निर्माण कार्य-03-सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-बृहत निर्माण कार्य से आदेश यू.ओ.- 39/35-3-2015, दिनांक 15 जनवरी, 2015 द्वारा पुर्नविनियोग के माध्यम से स्वीकृत की जा रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457 / दस-2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या- 1/2015/40(1)/1(20)2014/ 35-3-2015

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3- मण्डलायुक्त, बरेली मण्डल।
4- महालेखाकार, प्रथम(लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद, उ0प्र0 महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) इलाहाबाद ।
5- निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ ।
7- अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेव साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8- कोषाधिकारी, पीलीभीत ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5 ।
10- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) बरेली मण्डल।
11- अर्थ एवं संख्याधिकारी, पीलीभीत ।
12- राज्य योजना आयोग-।
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**